BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 249 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Narendra Kushwaha & Ors .....Applicants

Versus

Union of India & Ors .....Respondents

INDEX

Sr. no	Particulars	Page no.
01	Additional Submission With Affidavit	1-10
02	to the Photograph of Sarai Barai Wetland	11-33
03		

दिनांक 14.05.2026

आवेदक

नरेन्द्र कुशवाहा
(आर.टी.आई. एवं पर्यावरण कार्यकर्ता)
पता- पिछोर, थाना नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश 284128
ई-मेल-narendrakumarjhansi82@gmial.com
मो. 9452041529

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 249 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Narendra Kushwaha & Ors .....Applicants

Versus

Union of India & Ors .....Respondents

Additional Submission With Affidavit

Hon'ble Sirs,

The Applicant most respectfully submits the following point-wise additional affidavit before this Hon'ble Tribunal and is placing the true and factual position before this Hon'ble Tribunal through the following facts and evidences:—

"It is most respectfully prayed before the Hon'ble Sirs that, in the interest of environmental protection and justice, this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to duly examine and consider all the facts, evidences, records and circumstances stated in the present additional affidavit, and thereafter pass such appropriate orders as may be deemed fit and proper for taking necessary further action in the matter."

1. यह कि प्रतिवादी संख्या–6 द्वारा दिनांक 06.03.2026 को प्रस्तुत उत्तर/प्रत्युत्तर असत्य, भ्रामक, तथ्यविपरीत, मनगढ़ंत एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या–6 द्वारा प्रस्तुत कथनों का वास्तविक एवं तथ्यात्मक स्थिति से कोई सामंजस्य नहीं है।
That the reply/response submitted by Respondent No. 6 on 06.03.2026 is false, misleading, contrary to facts, fabricated and has been filed with the intention of concealing the true and material facts from this Hon'ble Tribunal. The statements made by Respondent No. 6 have no nexus with the actual and factual position prevailing at the site.

2. यह कि माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 12.12.2025 को प्रतिवादी संख्या–3, 5 एवं 6 को स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि प्रश्नगत जल निकायों में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न होने पाए। तथापि उक्त न्यायिक निर्देशों के बावजूद वर्तमान समय में भी संबंधित जल निकाय एवं उसके बफर क्षेत्र में निर्माण कार्य निरंतर जारी है।
That this Hon'ble Tribunal, vide order dated 12.12.2025, had specifically directed Respondent Nos. 3, 5 and 6 to ensure that no illegal construction takes place in the water bodies in question. However, despite the aforesaid judicial directions, construction activities are still continuously going on in the concerned water body and its buffer zone even at present.

3. यह कि उक्त प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पारित आदेश के माध्यम से आवेदक को यह अनुमति प्रदान की गई थी कि वह प्रश्नगत जल निकाय एवं उसके बफर क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य से संबंधित प्रासंगिक सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत कर सकता है।
That in the present matter, this Hon'ble Tribunal, vide order dated 09.03.2026, was pleased to permit the Applicant to place on record relevant material relating to the ongoing construction activities in the water body in question and its buffer zone.

P.T.O. 02

4. यह कि दिनांक 06.03.2026 को प्रतिवादी संख्या–6 (जिलाधिकारी, बाराबंकी) द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष जानबूझकर मिथ्या, तथ्यविपरीत एवं भ्रामक प्रत्युत्तर/शपथपत्र प्रस्तुत कर माननीय अधिकरण को वास्तविक तथ्यों से गुमराह करने तथा प्रश्नगत जल निकाय एवं उसके बफर क्षेत्र में संचालित अवैध निर्माण गतिविधियों को छिपाने का सुनियोजित प्रयास किया गया है। प्रतिवादी संख्या–6 का यह कृत स्पष्ट रूप से न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता, निष्पक्षता एवं विधि के शासन के विरुद्ध होने के साथ-साथ माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशों की अवमानना एवं न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना तथा वास्तविक तथ्यों से गुमराह करने के गंभीर प्रयास की श्रेणी में आता है।

That on 06.03.2026, Respondent No. 6 (District Magistrate, Barabanki), by deliberately submitting a false, factually incorrect and misleading reply/affidavit before this Hon'ble Tribunal, has made a calculated attempt to mislead this Hon'ble Tribunal regarding the true facts and to conceal the illegal construction activities being carried out in the water body in question and its buffer zone. The aforesaid act of Respondent No. 6 is clearly against the sanctity of judicial proceedings, fairness and the rule of law, and further amounts to disobedience of the orders passed by this Hon'ble Tribunal, obstruction in the administration of justice, and a serious attempt to suppress and misrepresent the true factual position before this Hon'ble Tribunal.

5. यह कि दिनांक 06.03.2026 को प्रतिवादी संख्या–6 (जिलाधिकारी, बाराबंकी) द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष जानबूझकर तथ्यविपरीत एवं भ्रामक प्रत्युत्तर/शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि प्रश्नगत जल निकाय एवं उसके बफर क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, जबकि वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है तथा स्थल पर वर्तमान समय में अवैध निर्माण की गतिविधियाँ निरंतर जारी हैं। जिसे आवेदक द्वारा दाखिल रिजॉइंडर दिनांक 09.12.2025 में संलग्न फोटोग्राफों तथा वर्तमान अतिरिक्त शपथपत्र/प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जीपीएस टैगयुक्त फोटोग्राफों में स्पष्ट रूप से दिखाया एवं बताया गया है, जिनमें स्थल पर जारी निर्माण गतिविधियाँ प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती हैं।

That on 06.03.2026, Respondent No. 6 (District Magistrate, Barabanki) deliberately filed a factually incorrect and misleading reply/affidavit before this Hon'ble Tribunal stating therein that no construction activity was taking place in the water body in question and its buffer zone, whereas the actual factual position is entirely contrary thereto and illegal construction activities are continuously going on at the site even at present. The same has been clearly demonstrated and brought on record through the photographs annexed with the Rejoinder dated 09.12.2025 filed by the Applicant as well as through the GPS-tagged photographs annexed with the present Additional Affidavit/Application, wherein the ongoing construction activities at the site are visibly evident.

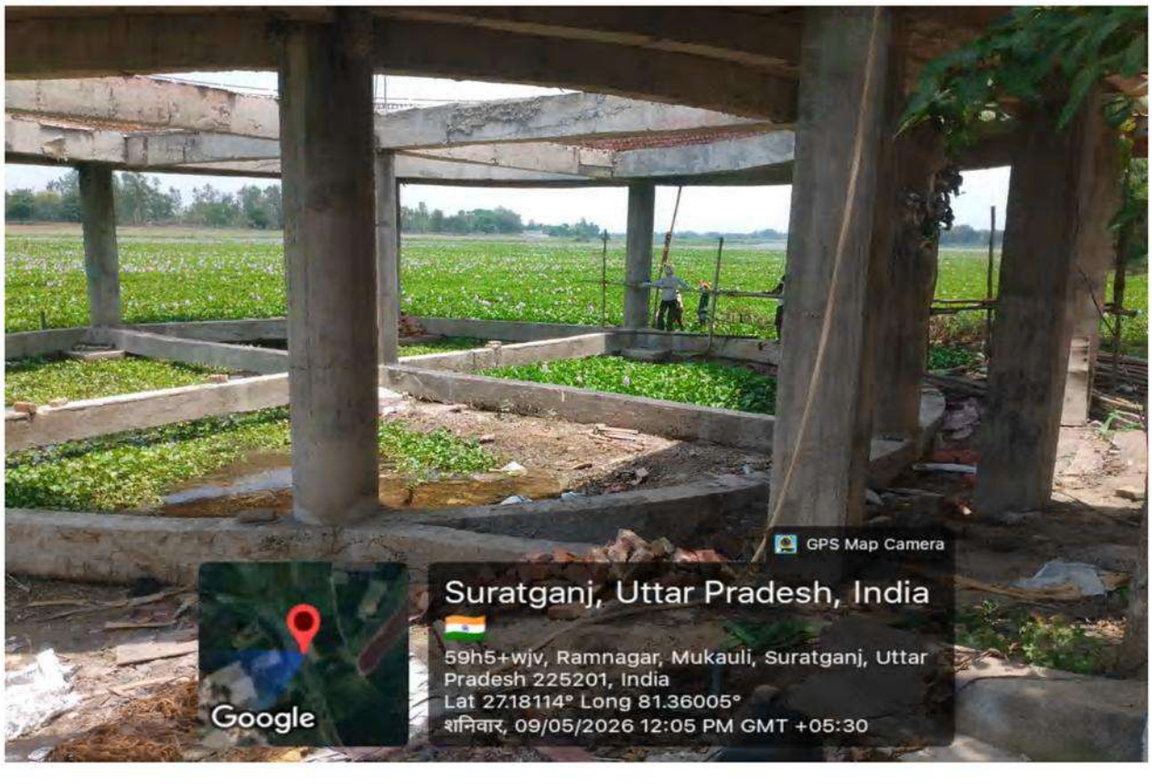

6. यह कि माननीय अधिकरण के समक्ष जानबूझकर मिथ्या, तथ्यविपरीत एवं भ्रामक प्रत्युत्तर/शपथपत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरांत भी यदि प्रतिवादी संख्या–6 के विरुद्ध विधिसम्मत एवं कठोर कार्यवाही नहीं की जाती है, तो इससे न केवल न्यायिक आदेशों की प्रभावशीलता एवं न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बल्कि भविष्य में अन्य अधिकारियों/प्रतिवादीगण को भी न्यायालयों एवं अधिकरणों के समक्ष भ्रामक एवं असत्य तथ्य प्रस्तुत करने का प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी स्थिति विधि के शासन, न्यायिक अनुशासन एवं पर्यावरणीय न्याय व्यवस्था में आमजन के विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।

That if, despite the deliberate filing of false, factually incorrect and misleading reply/affidavit before this Hon'ble Tribunal, no lawful and stringent action is taken against Respondent No. 6, the same would not only adversely affect the efficacy of judicial orders and the sanctity of judicial proceedings, but would also encourage other officials/respondents in future to place misleading and false facts before Courts and Tribunals. Such a situation is likely to seriously undermine public confidence in the rule of law, judicial discipline and the environmental justice delivery system.

7. यह कि आवेदक द्वारा दिनांक 09.05.2026 को स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि संबंधित स्थल पर वर्तमान समय में भी अवैध निर्माण निरंतर गतिविधियाँ जारी हैं। स्थल पर श्रमिकों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था तथा पक्के निर्माण एवं कंक्रीटकरण के कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। आवेदक द्वारा स्थल के जीपीएस टैगयुक्त फोटोग्राफ लिए गए हैं, जिनमें दिनांक, समय एवं लोकेशन अंकित है। उक्त फोटोग्राफ यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि माननीय अधिकरण के आदेशों के बावजूद निर्माण गतिविधियाँ निरंतर जारी हैं।

That the Applicant conducted a site inspection on 09.05.2026, during which it was found that illegal construction activities are still continuously going on at the concerned site. Construction work was being carried out by labourers at the site, and permanent constructions and concretization activities were clearly visible. The Applicant has taken GPS-tagged photographs of the site, bearing the date, time and location details. The said photographs clearly demonstrate that, despite the orders passed by this Hon'ble Tribunal, the construction activities are continuously continuing at the site.

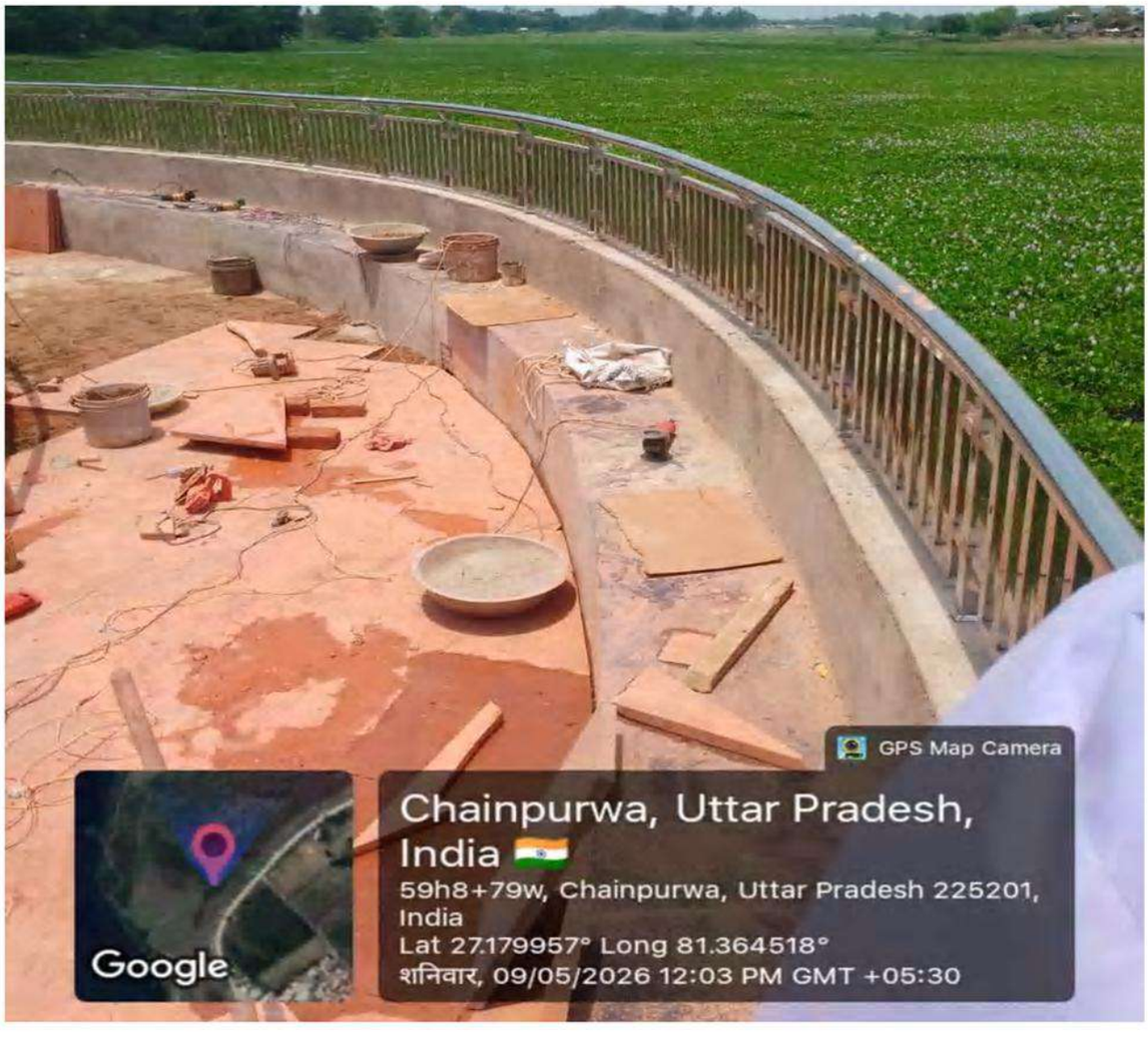

8. यह कि माननीय अधिकरण द्वारा अवैध निर्माण रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद प्रश्नगत जल निकाय एवं उसके बफर क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रहने से आमजन एवं पर्यावरण प्रेमियों के मन में यह धारणा उत्पन्न हो रही है कि न्यायिक आदेश मात्र कागजी कार्यवाही बनकर रह गए हैं तथा संबंधित विभाग एवं अधिकारी न्यायालयीय निर्देशों के अनुपालन के प्रति गंभीर नहीं हैं।

That despite the specific directions issued by this Hon'ble Tribunal to stop the illegal construction activities, the continued construction in the water body in question and its buffer zone is creating an impression in the minds of the general public and environmentalists that judicial orders have been reduced to mere paper formalities and that the concerned departments and officials are not serious about complying with the directions issued by the Courts and Tribunals.

9. यह कि जिन अधिकारियों एवं विभागों को जल निकायों एवं पर्यावरण संरक्षण की संवैधानिक, वैधानिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है, यदि वही जल निकायों एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाले कार्यों में संलिप्त पाए जाएँ तथा माननीय अधिकरण के स्पष्ट आदेशों का भी पालन न करें, तो ऐसी स्थिति पर्यावरणीय शासन व्यवस्था, विधि के शासन तथा जनविश्वास के लिए अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक है।

That if the very officials and departments upon whom the constitutional, statutory and administrative responsibility of protecting water bodies and the environment has been entrusted are themselves found involved in activities causing damage to the water bodies and the environment, and further fail to comply with the clear directions issued by this Hon'ble Tribunal, such a situation becomes extremely serious and alarming for environmental governance, the rule of law and public confidence in the justice delivery system.

10. यह कि प्रश्नगत जल निकायों के भीतर लगभग 20 फीट ऊँचे एवं 100 फीट गोलाकार मिट्टी/मलबे के कई टिले बना दिए गए हैं, जो जल निकाय की प्राकृतिक संरचना, जलधारण क्षमता एवं प्राकृतिक जल प्रवाह को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। उक्त कृत्रिम संरचनाएँ न केवल जल निकाय के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर रही हैं, बल्कि इससे वर्षाजल संचयन, भूजल पुनर्भरण एवं स्थानीय पारिस्थितिक संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

That several circular mounds/heaps of soil/debris, approximately 20 feet high and about 100 feet in circumference, have been created within the water bodies in question, which are seriously affecting the natural structure, water holding capacity and natural flow of water in

the said water bodies. These artificial structures are not only altering the original character of the water bodies, but are also adversely affecting rainwater harvesting, groundwater recharge and the local ecological balance.

11. यह कि प्रश्नगत जल निकायों एवं उनके बफर क्षेत्रों में किए जा रहे तथाकथित "विकास कार्य" वास्तविक जनहित अथवा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से न होकर जनता के कर से प्राप्त सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं बंदरबांट का माध्यम बनते जा रहे हैं। माननीय अधिकरण के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद निर्माण गतिविधियों का निरंतर जारी रहना इस आशंका को और अधिक प्रबल करता है कि संबंधित परियोजनाओं को पर्यावरणीय नियमों, विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक आदेशों की अनदेखी करते हुए केवल वित्तीय लाभ एवं सार्वजनिक धन का बंदरबांट करने के उद्देश्य से आगे बढ़ाया जा रहा है।

That the so-called "development works" being carried out in the water bodies in question and their buffer zones do not appear to be in furtherance of any genuine public interest or environmental protection objective, but rather seem to have become a means for misuse and misappropriation of public funds derived from taxpayers' money. The continued execution of construction activities despite the clear directions issued by this Hon'ble Tribunal further strengthens the apprehension that the concerned projects are being carried forward in disregard of environmental norms, statutory provisions and judicial orders, solely for pecuniary gain and diversion/misuse of public funds.

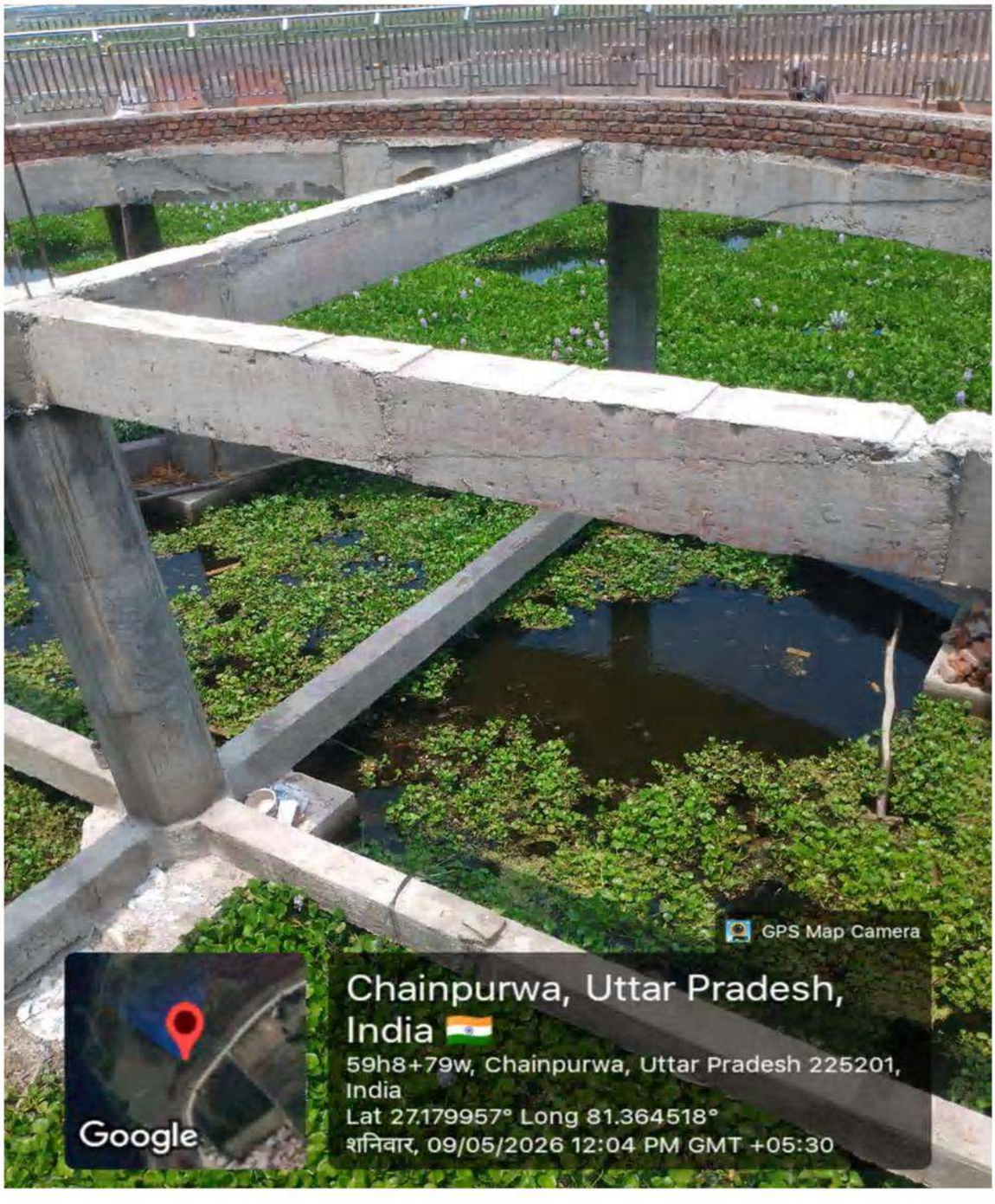

12. यह कि जनपद बाराबंकी स्थित प्रश्नगत "मगहर झील" पर कराए जा रहे निर्माण कार्यों का लोकार्पण दिनांक 22 मई 2023 को किया गया था, जिसका विवरण स्थल पर स्थापित शिलापट्ट/लोकार्पण पट्टिका पर अंकित है। उक्त स्थल पर वर्तमान समय में भी अवैध निर्माण, कंक्रीटकरण एवं अन्य अनधिकृत गतिविधियाँ निरंतर जारी हैं, जो प्रश्नगत जल निकाय की प्राकृतिक संरचना एवं पर्यावरणीय संतुलन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही हैं।

That the construction works being carried out at the water body in question, namely "Maghar Jheel" situated in District Barabanki, were inaugurated on 22 May 2023, the details whereof are inscribed on the foundation stone/inauguration plaque installed at the site. Even at present, illegal construction, concretization and other unauthorized activities are continuously going on at the said site, which are adversely affecting the natural structure and environmental balance of the water body in question.

13. यह कि प्रश्नगत जल निकायों एवं उनके बफर क्षेत्रों के अवैध निर्माण, कंक्रीटकरण एवं अन्य अनधिकृत गतिविधियों को अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज/फोटोग्राफ रिकॉर्ड संख्या 21 से 32, 47, 54, 107 से 110, 156, 157, 158 एवं 168 से 172 पर एवं इस अतिरिक्त शपथपत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

That the illegal constructions, concretization and other unauthorized activities being carried out in the water bodies in question and their buffer zones can be clearly seen from the documents/photographs available on record bearing Record Nos. 21 to 32, 47, 54, 107 to 110,

156, 157, 158 and 168 to 172, as well as from the materials annexed with the present Additional Affidavit.

14. यह कि भारतीय संविधान के भाग–IV के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत राज्य तथा उसके सभी विभागों और अधिकारियों पर यह संवैधानिक दायित्व निहित है कि वे पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करें तथा प्राकृतिक संसाधनों, जल निकायों, वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा सुनिश्चित करें। इसके बावजूद संबंधित विभागों एवं अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत जल निकाय एवं उसके बफर क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य होने देना अथवा स्वयं ऐसे कार्यों में संलिप्त होना उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रतिकूल है तथा पर्यावरणीय न्याय एवं विधि के शासन के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।
That under Article 48A of Part IV of the Constitution of India, the State and all its departments and authorities are under a constitutional obligation to protect and improve the environment and to safeguard natural resources, water bodies, forests and wildlife. Despite the same, permitting illegal construction activities in the water body in question and its buffer zone, or themselves being involved in such activities, is contrary to their constitutional duties and amounts to a gross violation of the principles of environmental justice and the rule of law.

15. यह कि माननीय अधिकरण के समक्ष प्रश्नगत जल निकायों एवं उनके बफर क्षेत्र पर किए जा रहे अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों की वास्तविक एवं तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि राजस्व अभिलेखों, मूल नक्शों एवं उपलब्ध सरकारी अभिलेखों के आधार पर प्रश्नगत जल निकायों एवं उनके बफर क्षेत्र का आधुनिक तकनीकों, जैसे डीजीपीएस (DGPS), ड्रोन सर्वेक्षण, सैटेलाइट इमेजरी एवं जीआईएस मैपिंग के माध्यम से विधिवत सीमांकन कराया जाए। ऐसा सीमांकन न केवल जल निकायों की वास्तविक सीमा एवं बफर क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट करेगा, बल्कि अवैध अतिक्रमण, भूमि परिवर्तन, कंक्रीटकरण एवं अनधिकृत निर्माण गतिविधियों की सही प्रकृति एवं सीमा भी माननीय अधिकरण के समक्ष स्थापित करने में सहायक होगा। साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध हस्तक्षेप को रोकने तथा प्रश्नगत जल निकायों के दीर्घकालिक संरक्षण एवं पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भी यह कार्यवाही अत्यंत आवश्यक एवं जनहित में है।

That in order to ascertain and place before this Hon'ble Tribunal the true and factual position regarding the illegal constructions and encroachments being carried out in the water bodies in question and their buffer zones, it is necessary that the said water bodies and their buffer zones be duly surveyed and demarcated on the basis of revenue records, original maps and available official records by using modern technologies such as DGPS survey, drone survey, satellite imagery and GIS mapping. Such demarcation would not only clarify the actual boundaries of the water bodies and their buffer zones, but would also assist in establishing before this Hon'ble Tribunal the true nature and extent of illegal encroachments, land alteration, concretization and unauthorized construction activities. Furthermore, such an exercise is also necessary and in the larger public interest to prevent any future illegal interference and to ensure the long-term protection and environmental security of the water bodies in question.

16. यह कि यह तथ्य अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक है कि प्रश्नगत जल निकायों से आसपास के क्षेत्रों के बड़े भूभाग में कृषि सिंचाई की जाती है। प्रश्नगत जल निकायों में किए जा रहे कंक्रीटकरण, अवैध निर्माण एवं प्राकृतिक जल प्रवाह में हस्तक्षेप के कारण उनकी जलधारण क्षमता, भूजल पुनर्भरण एवं प्राकृतिक जल संचयन प्रणाली प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है, जिससे भविष्य में कृषि सिंचाई व्यवस्था पर दीर्घकालिक एवं अपूरणीय दुष्प्रभाव उत्पन्न होने की गंभीर आशंका है।
That it is an extremely serious and alarming fact that irrigation of agricultural land over a large area of the surrounding regions is carried out through the water bodies in question. Due to concretization, illegal constructions, and interference with the natural water flow being carried out in the said water bodies, their water holding capacity, groundwater recharge, and natural water conservation system are being adversely affected, which gives rise to a serious

apprehension of long-term and irreparable adverse effects on the agricultural irrigation system in the future.

इस प्रकार प्रश्नगत जल निकायों का संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय विषय मात्र न होकर, बल्कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निहित संवैधानिक दायित्वों, सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत, सतत विकास सिद्धांत तथा एहतियाती सिद्धांत से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधिक एवं जनहित का विषय है, जिस पर माननीय अधिकरण का हस्तक्षेप न्याय, पर्यावरण संरक्षण एवं व्यापक जनहित की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य हो जाता है।

Thus, the protection of the water bodies in question is not merely an environmental issue, but also an important matter of legal and public interest concerning the constitutional obligations enshrined under the Constitution of India, the Public Trust Doctrine, the Principle of Sustainable Development, and the Precautionary Principle, upon which the intervention of this Hon'ble Tribunal becomes necessary and indispensable in the interest of justice, environmental protection, and larger public welfare.

PRAYER

In view of the facts and circumstances stated hereinabove, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to pass the following orders/directions in the interest of justice and environmental protection:—

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त शपथपत्र एवं उसके साथ संलग्न अतिरिक्त दस्तावेजों/जीपीएस टैगयुक्त फोटोग्राफों को अभिलेख पर लिया जाए।
   That the Additional Affidavit filed by the Applicant along with the annexed additional documents/GPS-tagged photographs may kindly be taken on record.

2. प्रतिवादी संख्या–6 (जिलाधिकारी, बाराबंकी) द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कथित मिथ्या, तथ्यविपरीत एवं भ्रामक प्रत्युत्तर/शपथपत्र का संज्ञान लेते हुए उसके संबंध में विधिसम्मत एवं उपयुक्त कार्यवाही किए जाने हेतु आदेश पारित किए जाएँ।
   That this Hon'ble Tribunal may kindly take cognizance of the alleged false, factually incorrect and misleading reply/affidavit submitted by Respondent No. 6 (District Magistrate, Barabanki) before this Hon'ble Tribunal and pass appropriate orders for initiating lawful and suitable action in accordance with law.

3. प्रतिवादीगण को तत्काल प्रभाव से प्रश्नगत जल निकायों एवं उनके बफर क्षेत्रों में संचालित समस्त अवैध निर्माण, कंक्रीटकरण एवं अन्य निर्माण गतिविधियों को रोकने/हटाने हेतु निर्देशित किया जाए।
   That the Respondents may kindly be directed to immediately stop/remove all illegal constructions, concretization and other construction activities being carried out in the water bodies in question and their buffer zones.

4. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना के संबंध में संबंधित अधिकारियों/विभागों के विरुद्ध उपयुक्त दंडात्मक कार्यवाही करने की कृपा की जाए।
   That this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to initiate appropriate punitive action against the concerned officials/departments for non-compliance and violation of the orders passed by this Hon'ble Tribunal.

5. प्रश्नगत जल निकायों एवं उनके बफर क्षेत्रों का राजस्व अभिलेखों, मूल नक्शों एवं उपलब्ध सरकारी अभिलेखों के आधार पर डीजीपीएस (DGPS), ड्रोन सर्वेक्षण, सैटेलाइट इमेजरी एवं जीआईएस मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के

माध्यम से वैज्ञानिक एवं विधिवत सीमांकन कर स्थायी सीमा-स्तंभ स्थापित करें तथा उसकी अनुपालन आख्या माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि प्रश्नगत क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माण की गतिविधियों की वास्तविक स्थिति एवं सत्यता स्पष्ट रूप से सामने आ सके।

That the water bodies in question and their buffer zones may kindly be scientifically and duly surveyed/demarcated on the basis of revenue records, original maps and available official records by using modern technologies such as DGPS survey, drone survey, satellite imagery and GIS mapping, and permanent boundary pillars be installed thereon. The concerned authorities may further be directed to submit a compliance report before this Hon'ble Tribunal so that the true and factual position regarding the illegal encroachments and unauthorized construction activities carried out in the said area may clearly come on record before this Hon'ble Tribunal.

6. प्रश्नगत जल निकायों एवं उनके बफर क्षेत्रों में किए गए अवैध निर्माणों, कृत्रिम टीलों, कंक्रीटकरण एवं अन्य पर्यावरणीय क्षति का स्वतंत्र पर्यावरणीय मूल्यांकन कराए जाने तथा दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु आदेश पारित किए जाएँ।

   That appropriate orders may kindly be passed for conducting an independent environmental assessment/evaluation of the illegal constructions, artificial mounds, concretization and other environmental damage caused in the water bodies in question and their buffer zones, and for ensuring recovery of environmental compensation and initiation of other appropriate legal proceedings against the persons/officials found responsible.

7. माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 12.12.2025 एवं 09.03.2026 को पारित आदेशों के अनुपालन की निगरानी हेतु संबंधित विभागों/अधिकारियों से समयबद्ध अनुपालन आख्या प्रस्तुत कराए जाने का निर्देश दिया जाए।

   That the concerned departments/authorities may kindly be directed to submit a time-bound compliance report for monitoring the implementation and compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal dated 12.12.2025 and 09.03.2026.

8. न्यायहित, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रश्नगत जल निकायों की सुरक्षा हेतु माननीय अधिकरण जो अन्य उचित एवं आवश्यक आदेश/निर्देश पारित करना उचित समझे, पारित करने की कृपा करे।

   That this Hon'ble Tribunal may further be pleased to pass such other and further order(s)/direction(s) as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice, environmental protection and protection of the water bodies in question.

दिनांक 14.05.226

आवेदक

नरेन्द्र कुशवाहा
(आर.टी.आई. एवं पर्यावरण कार्यकर्ता)
पता- पिछोर, थाना नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश 284128
ई-मेल-narendrakumarjhansi82@gmial.com
मो. 9452041529

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 249 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Narendra Kushwaha & Ors .....Applicants

Versus

Union of India & Ors .....Respondents

शपथ-पत्र

शपथकर्ता मिनजानिव- नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्नालाल कुशवाहा पता- पिछोर, थाना नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश 284128

मैं शपथकर्ता उपरोक्त शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूं:-

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रकरण में आवेदक है एवं हालात प्रकरण से पूरी तरह से वाकिफ हैं। तथा अतिरिक्त सबमिशन देने में सक्षम है।
2. यह कि शपथकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अतिरिक्त सबमिशन प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. यह कि शपथकर्ता द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त सबमिशन में सही-सही तथ्यों में तहरीर किया गया है। जिन्हें पुनः संक्षिप्ता के कारण शपथपत्र में दोहराया नहीं जा रहा है इसलिए उन्हें इस शपथपत्र में अडॉप्ट किया जा रहा है जो इस शपथपत्र का भाग माना जावें।

मैं शपथकर्ता तस्दीक करता हूं कि वर्तमान शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरे निजी ज्ञान और जानकारी अनुसार सब सत्य और सही है तथा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह तस्दीक आज दिनांक 14.05.2026 को वमुकाम अहाता कचहरी झांसी में की गयी।

शपथकर्ता

Serial No. 3192 Date 14/5/26
Certified that the foregoing statement
sworn before me this day at 1:10 PM
by shri ..... to
whom the contents of this affidavit
have been read over and explained and
who is identified by ...
Received the legal fee Rs. 35/- each

SATISH KUMAR TRIPATHI
Advocate
Notary Govt. of India, Jhansi

लोकार्पण
महादेवा इको पर्यटन स्थल (भगहर झील) जनपद बाराबंकी
का लोकार्पण आज दिनांक 22 मई 2023 को
मुख्य अतिथि
डा. अरूण कुमार सक्सेना
मा. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र.
एवं
विशिष्ट अतिथि
श्री के.पी.मलिक
मा. राज्य मंत्री, वन ,पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र.
के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ।
श्रीमती ममता संजीव दूबे
आई.एफ.एस.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
श्री मनोज सिंह
आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
डा. अनिरूद्ध पाण्डेय
आई.एफ.एस.
वन संरक्षक/ क्षेत्रीय निदेशक,
सरयू वृत्त, अयोध्या
श्रीमती रेणु सिंह
आई.एफ.एस.
मुख्य वन संरक्षक(मध्य क्षेत्र)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
डा. एन.के.सिंह
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
बाराबंकी
श्री पी.के.सिंह
क्षेत्रीय वन अधिकारी फतेहपुर
श्री रूस्तम परवेज
प्रभागीय वनाधिकारी
बाराबंकी
GPS Map Camera
Jogamau, Uttar Pradesh, India
Jogamau, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.175253° Long 81.369843°
शनिवार, 09/05/2026 12:45 PM GMT +05:30
Google

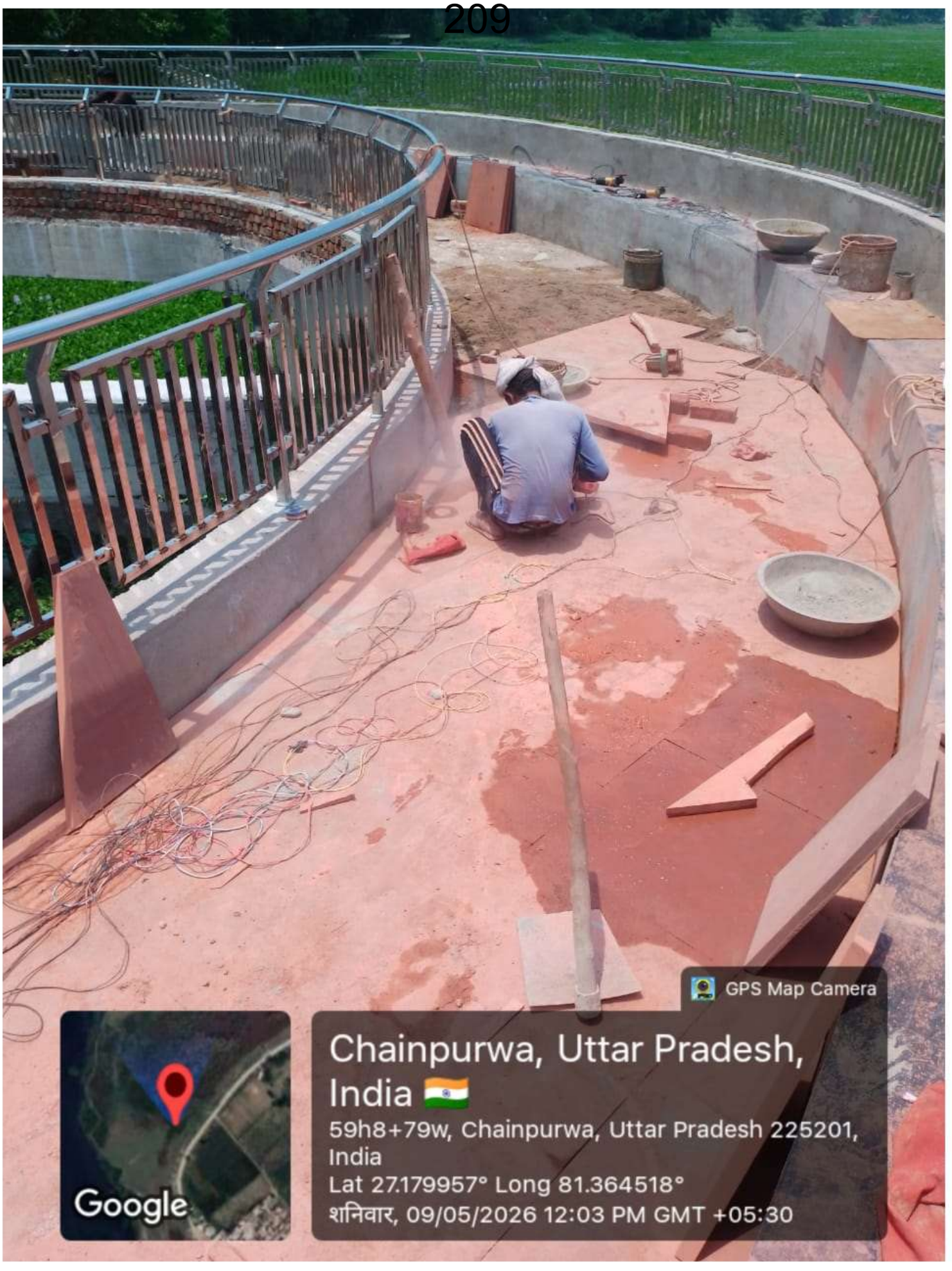
GPS Map Camera
Chainpurwa, Uttar Pradesh, India
59h8+79w, Chainpurwa, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.179957° Long 81.364518°
शनिवार, 09/05/2026 12:03 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Jogamau, Uttar Pradesh, India
Jogamau, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.175021° Long 81.369686°
शनिवार, 09/05/2026 12:35 PM GMT +05:30
Google

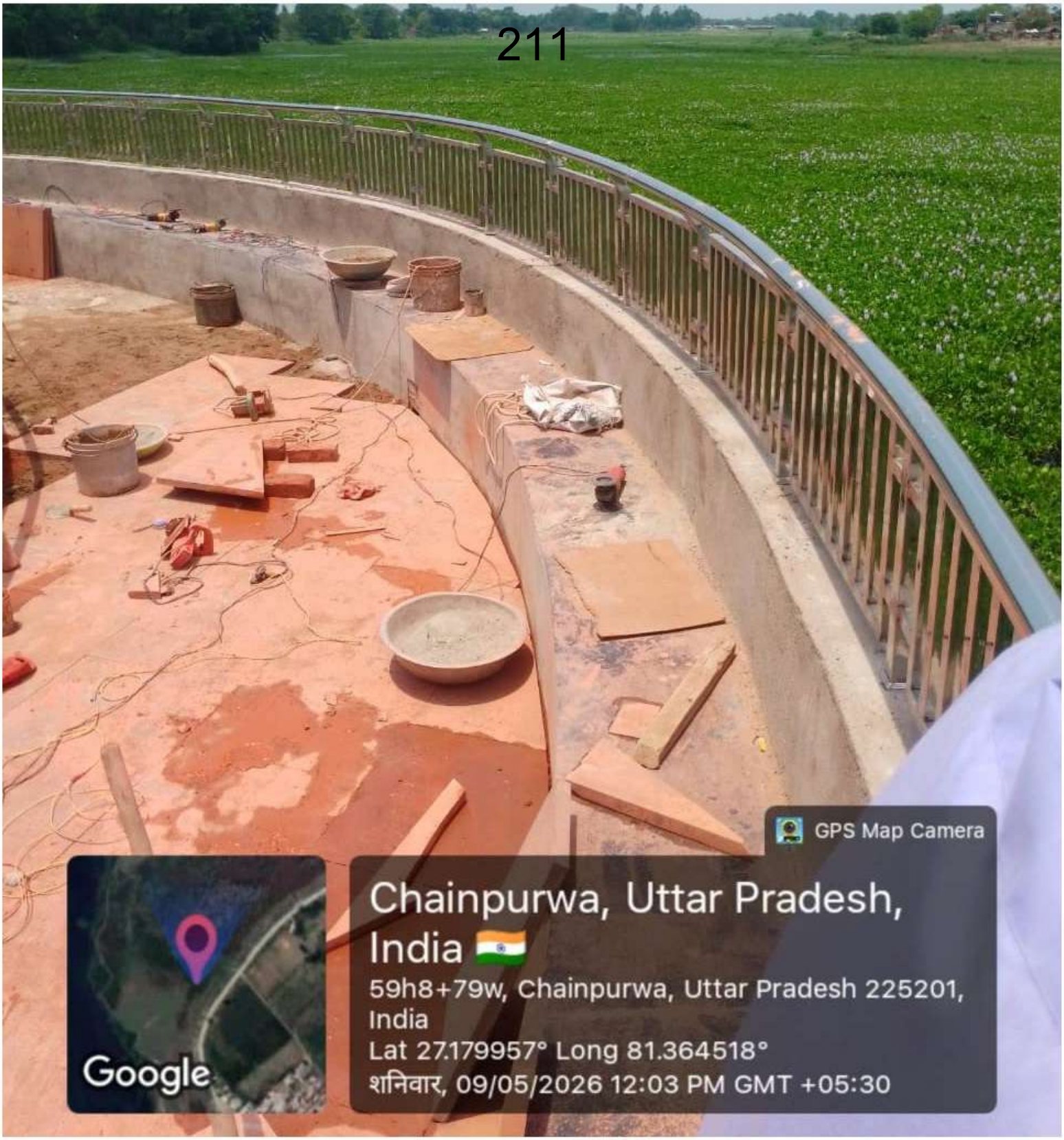
GPS Map Camera
Chainpurwa, Uttar Pradesh, India
59h8+79w, Chainpurwa, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.179957° Long 81.364518°
शनिवार, 09/05/2026 12:03 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Shahpur, Uttar Pradesh, India
59g7+7v9 Bhaghar Taal Ashram, Shahpur, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.17528° Long 81.367585°
शनिवार, 09/05/2026 12:52 PM GMT +05:30
Google

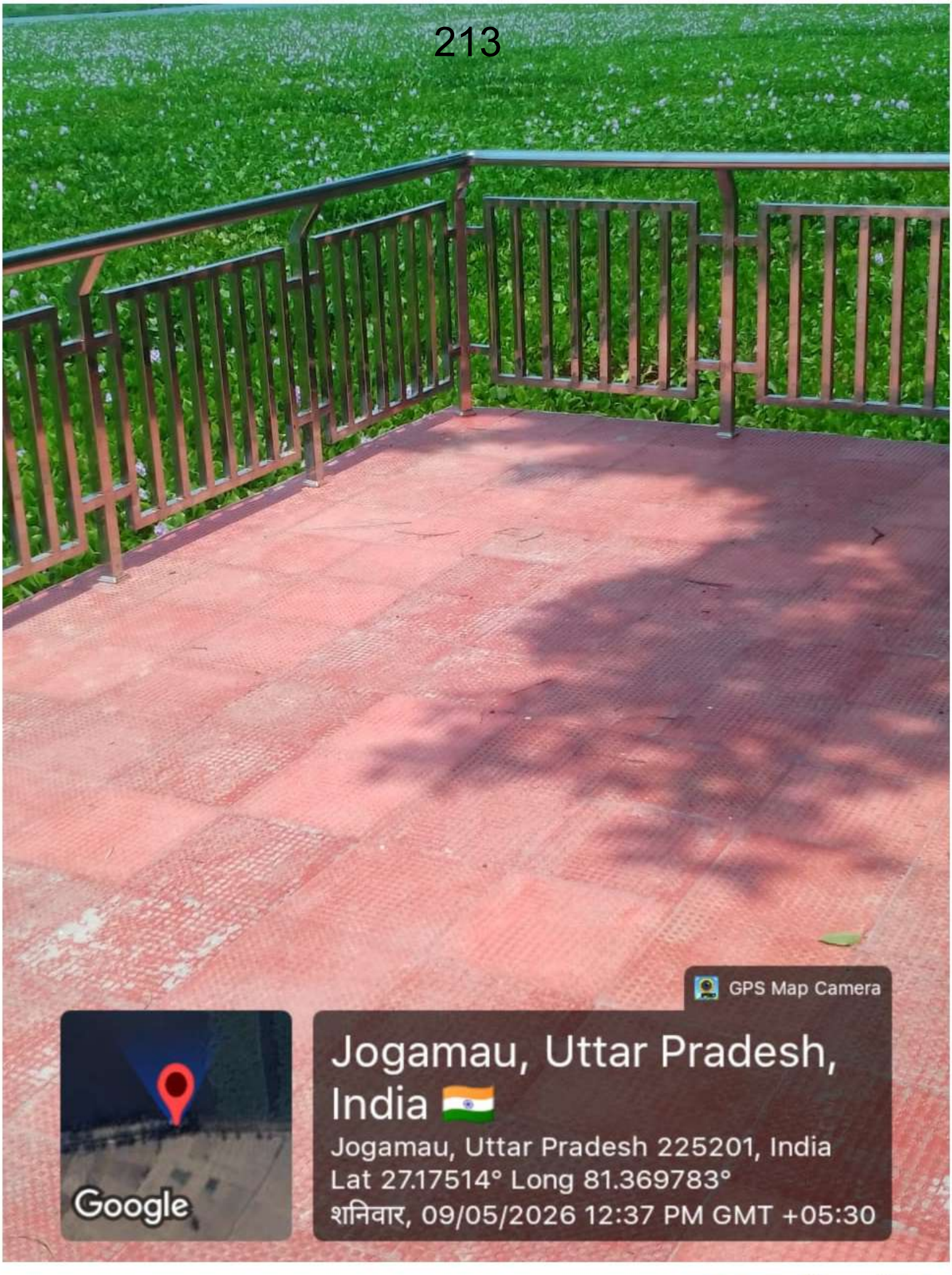
GPS Map Camera
Jogamau, Uttar Pradesh, India
Jogamau, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.17514° Long 81.369783°
शनिवार, 09/05/2026 12:37 PM GMT +05:30
Google

P.T.O. 17

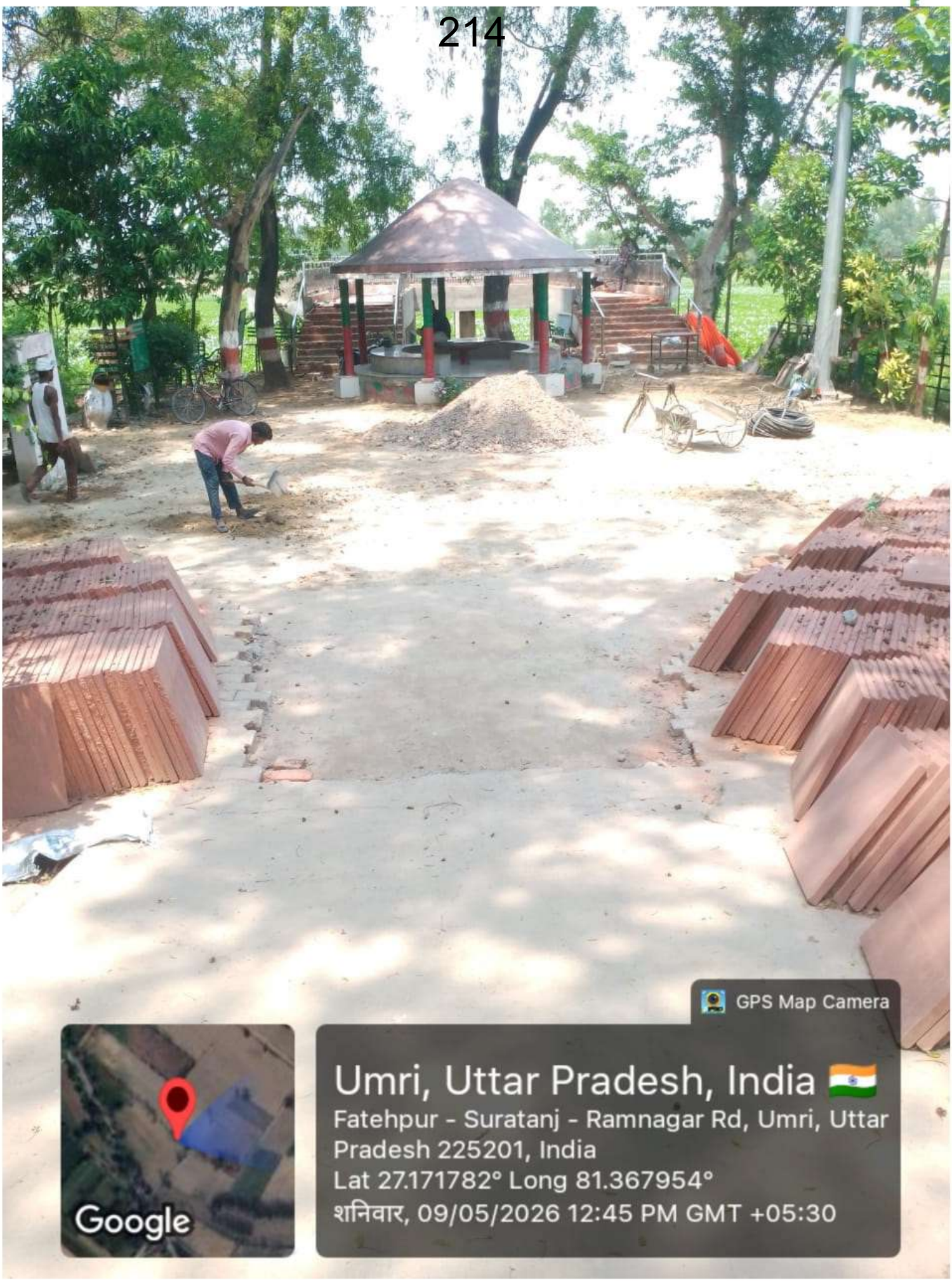
GPS Map Camera
Umri, Uttar Pradesh, India
Fatehpur - Suratanj - Ramnagar Rd, Umri, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.171782° Long 81.367954°
शनिवार, 09/05/2026 12:45 PM GMT +05:30
Google

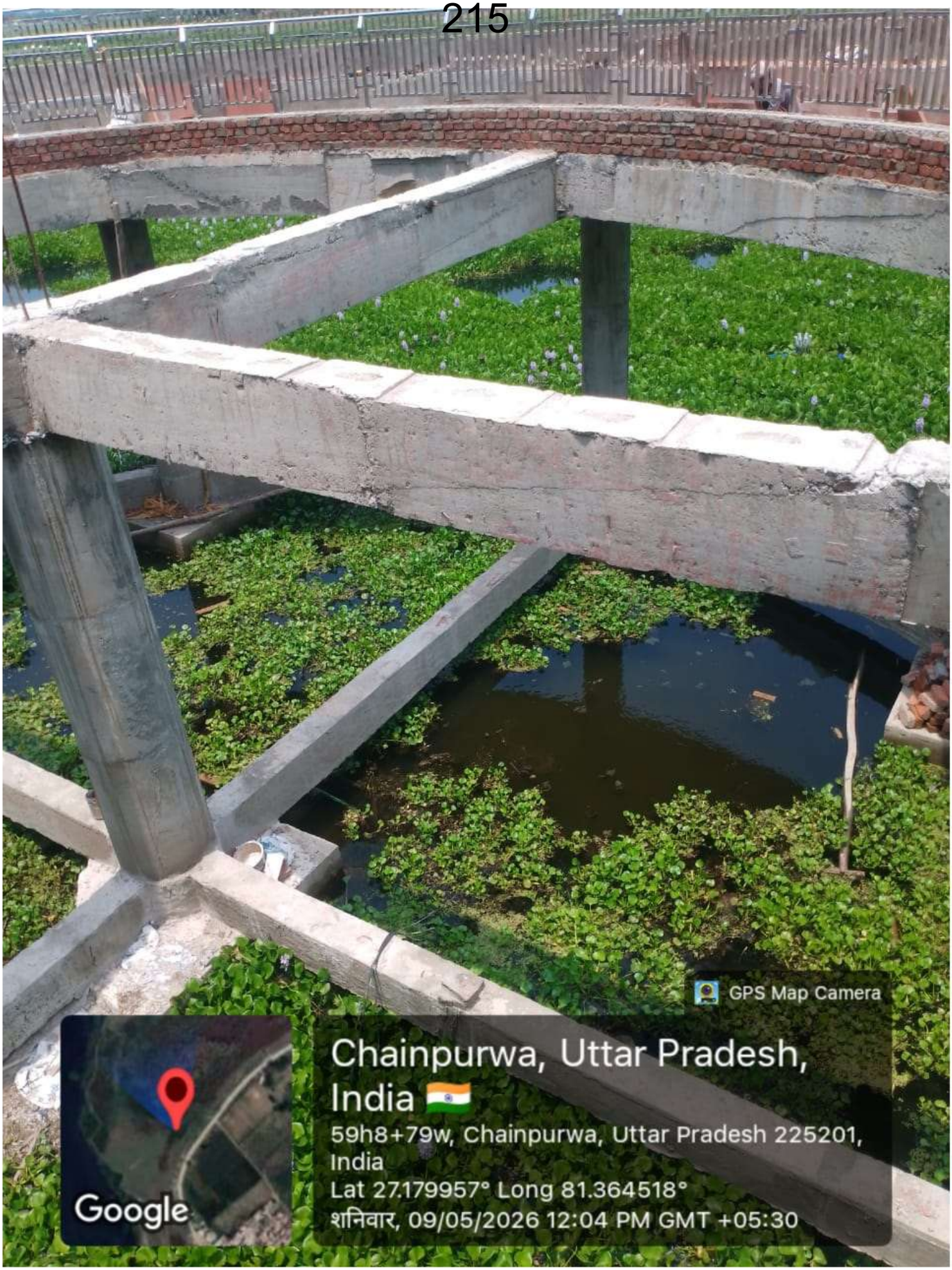
GPS Map Camera
Chainpurwa, Uttar Pradesh, India
59h8+79w, Chainpurwa, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.179957° Long 81.364518°
शनिवार, 09/05/2026 12:04 PM GMT +05:30
Google

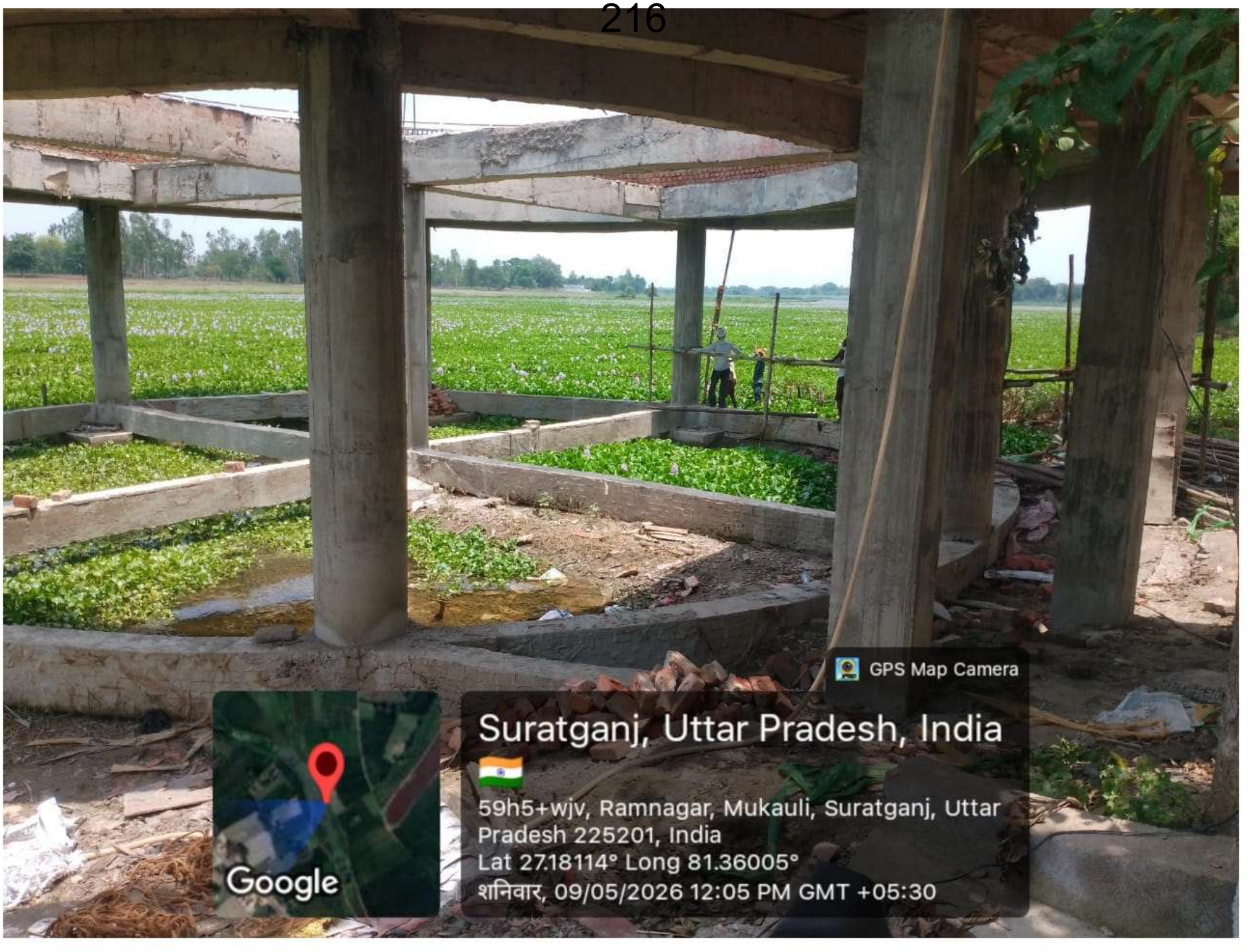
GPS Map Camera
Suratganj, Uttar Pradesh, India
59h5+wjv, Ramnagar, Mukauli, Suratganj, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.18114° Long 81.36005°
शनिवार, 09/05/2026 12:05 PM GMT +05:30
Google

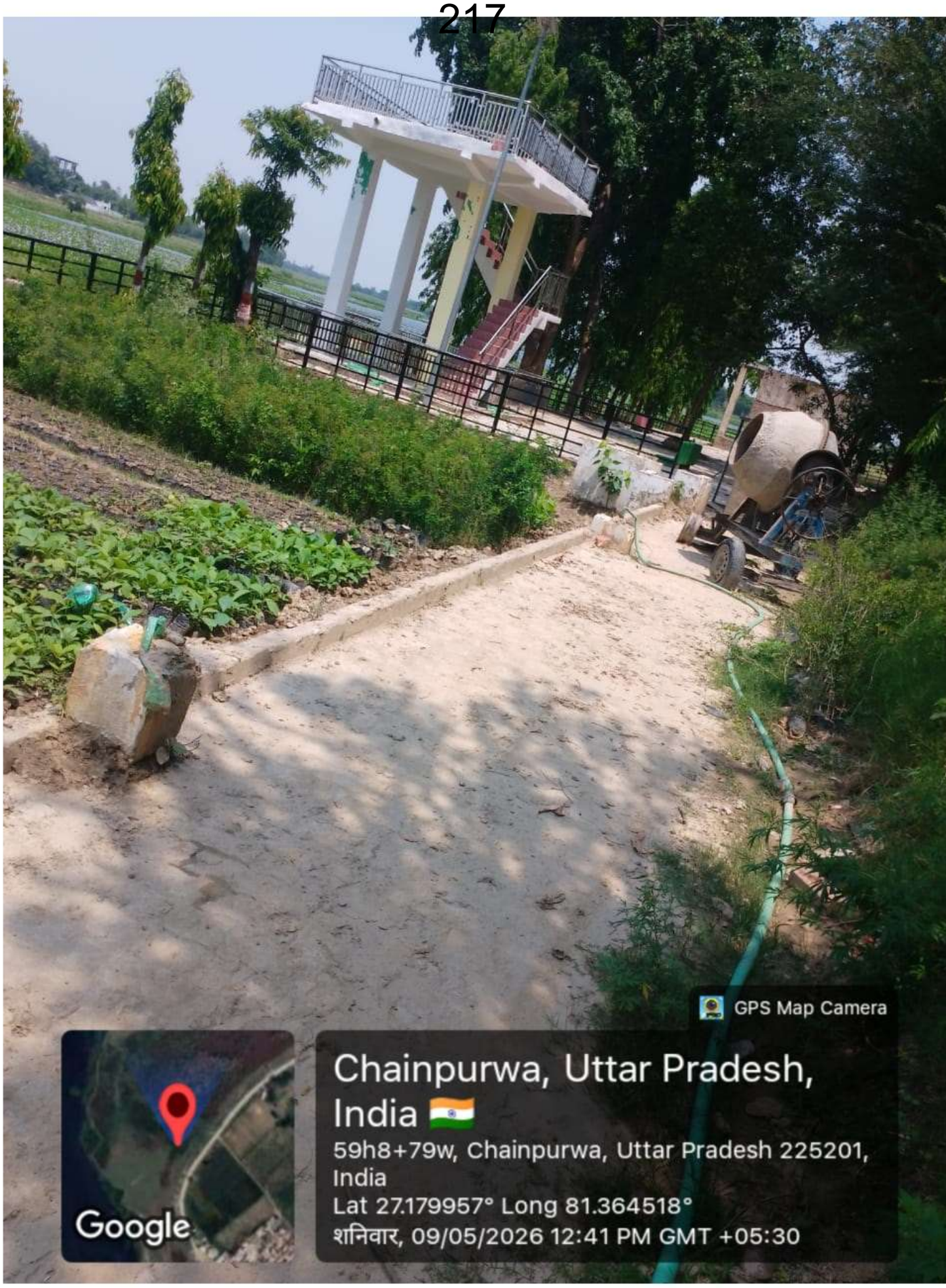
GPS Map Camera
Chainpurwa, Uttar Pradesh, India
59h8+79w, Chainpurwa, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.179957° Long 81.364518°
शनिवार, 09/05/2026 12:41 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Shahpur, Uttar Pradesh, India
59g7+7v9 Bhaghar Taal Ashram, Shahpur, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.175° Long 81.366923°
शनिवार, 09/05/2026 12:07 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Shahpur, Uttar Pradesh, India
59g7+7v9 Bhaghar Taal Ashram, Shahpur, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.175° Long 81.366923°
शनिवार, 09/05/2026 12:32 PM GMT +05:30
Google

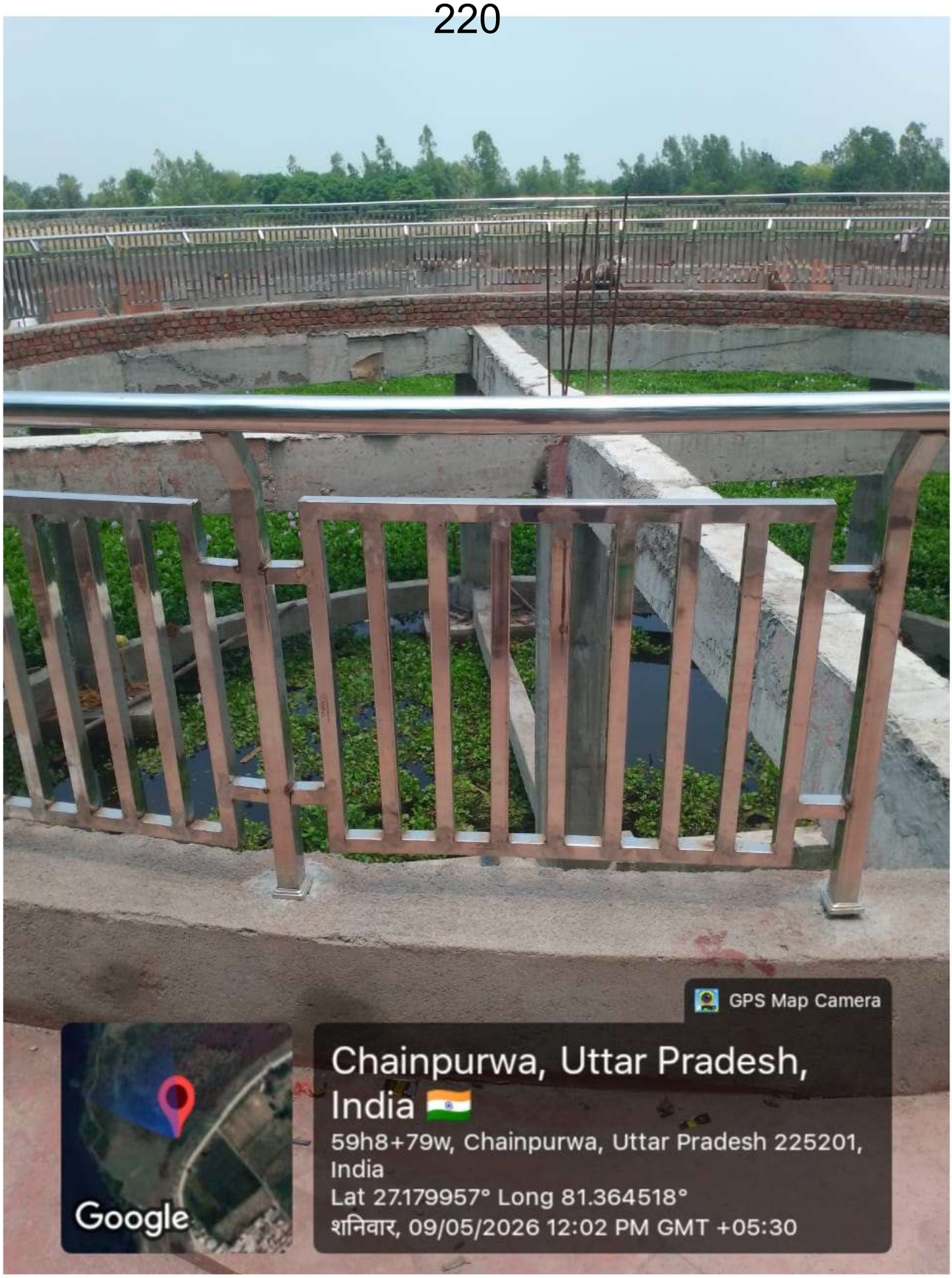
GPS Map Camera
Chainpurwa, Uttar Pradesh, India
59h8+79w, Chainpurwa, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.179957° Long 81.364518°
शनिवार, 09/05/2026 12:02 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Chainpurwa, Uttar Pradesh, India
59h8+79w, Chainpurwa, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.179957° Long 81.364518°
शनिवार, 09/05/2026 12:31 PM GMT +05:30
Google

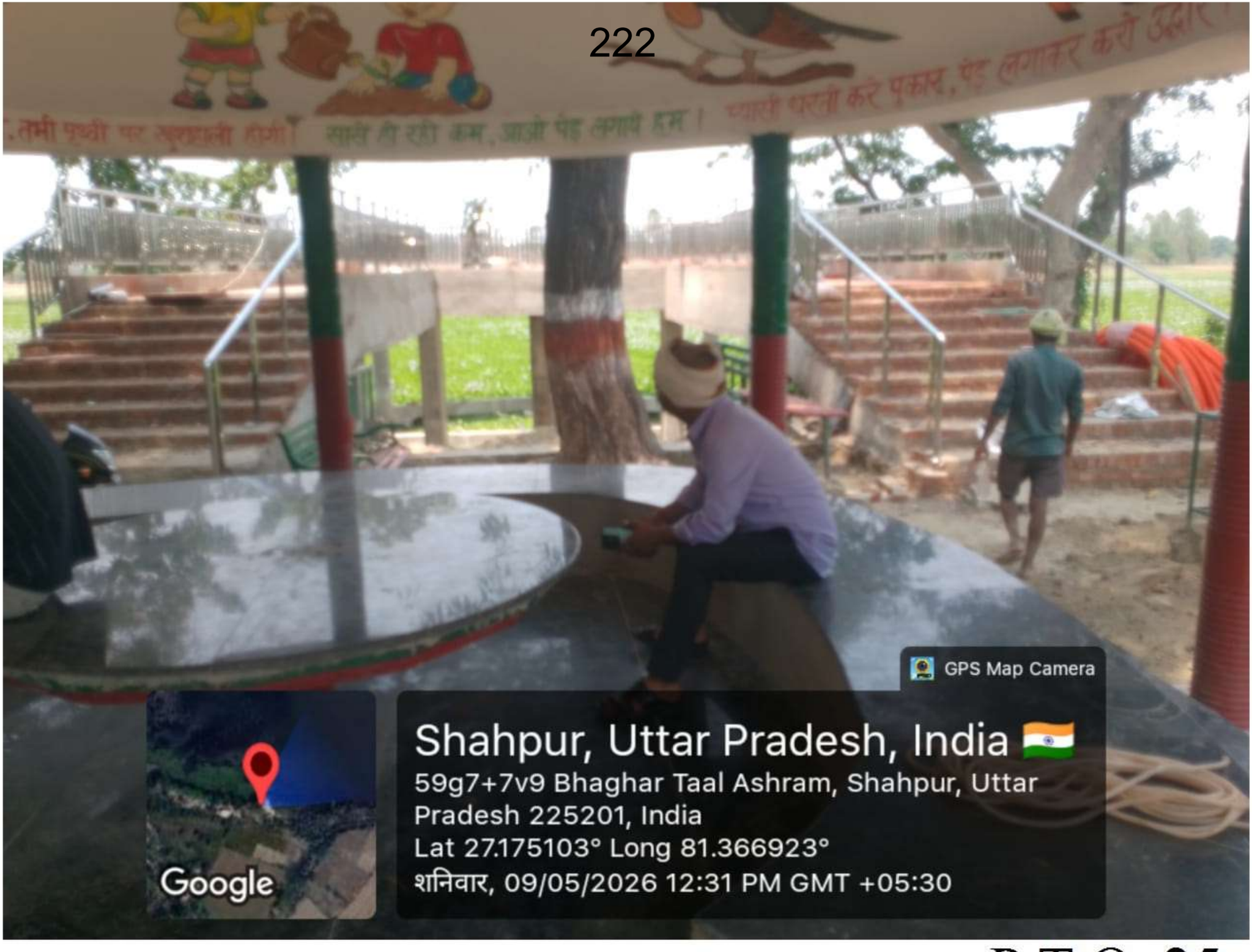
GPS Map Camera
Shahpur, Uttar Pradesh, India
59g7+7v9 Bhaghar Taal Ashram, Shahpur, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.175103° Long 81.366923°
शनिवार, 09/05/2026 12:31 PM GMT +05:30
Google

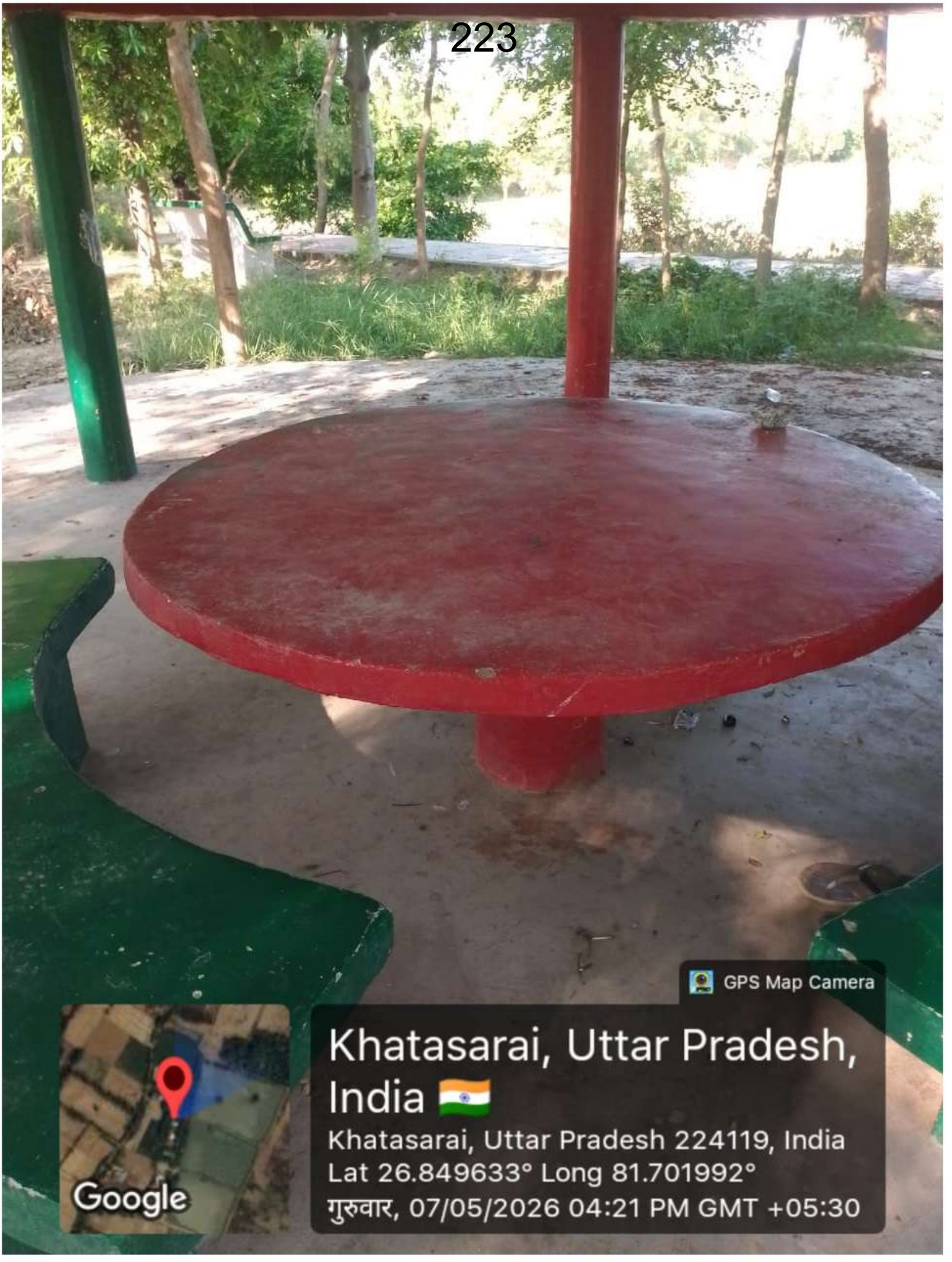
GPS Map Camera
Khatasarai, Uttar Pradesh, India
Khatasarai, Uttar Pradesh 224119, India
Lat 26.849633° Long 81.701992°
गुरुवार, 07/05/2026 04:21 PM GMT +05:30
Google

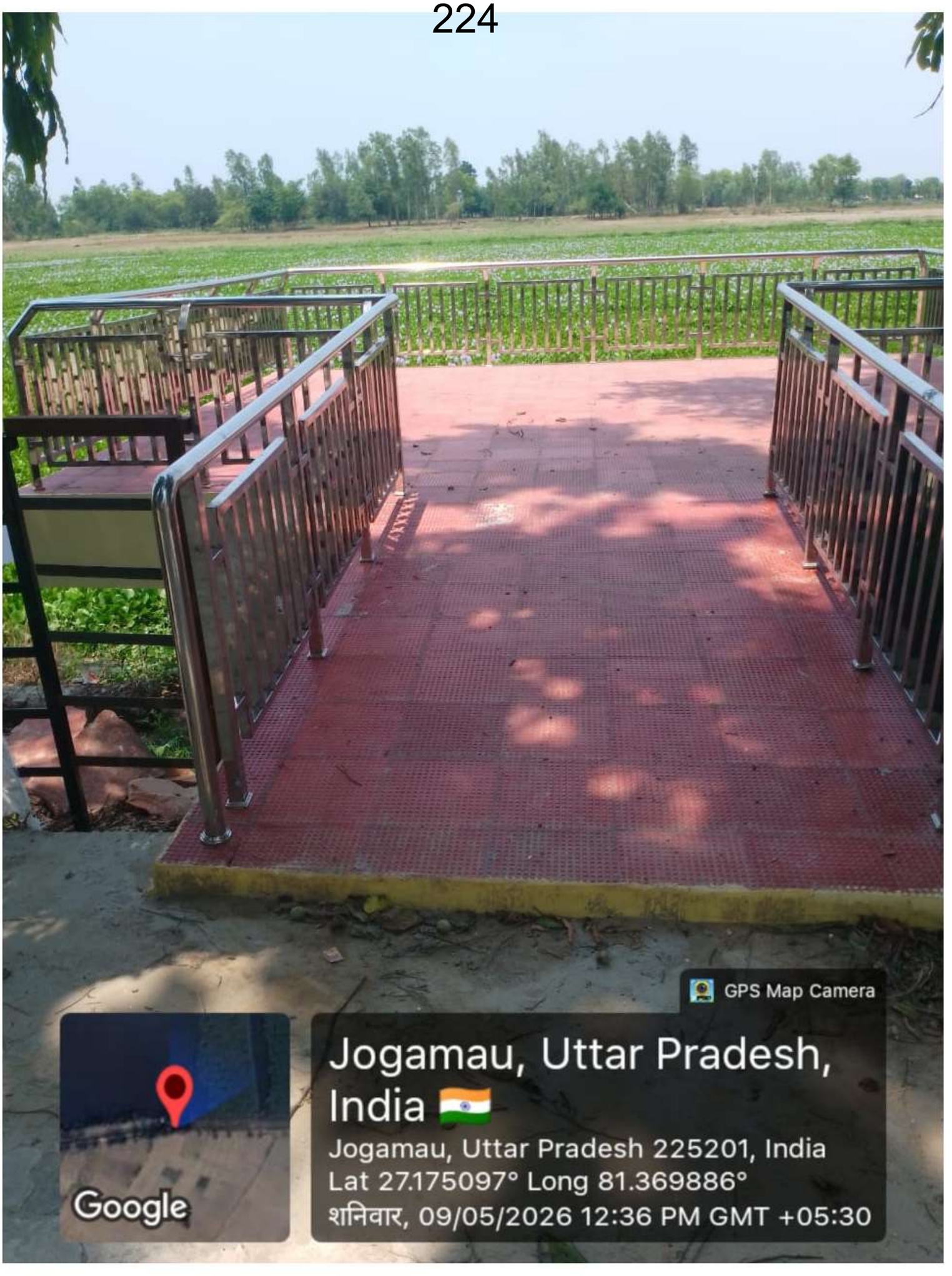
GPS Map Camera
Jogamau, Uttar Pradesh, India
Jogamau, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.175097° Long 81.369886°
शनिवार, 09/05/2026 12:36 PM GMT +05:30
Google

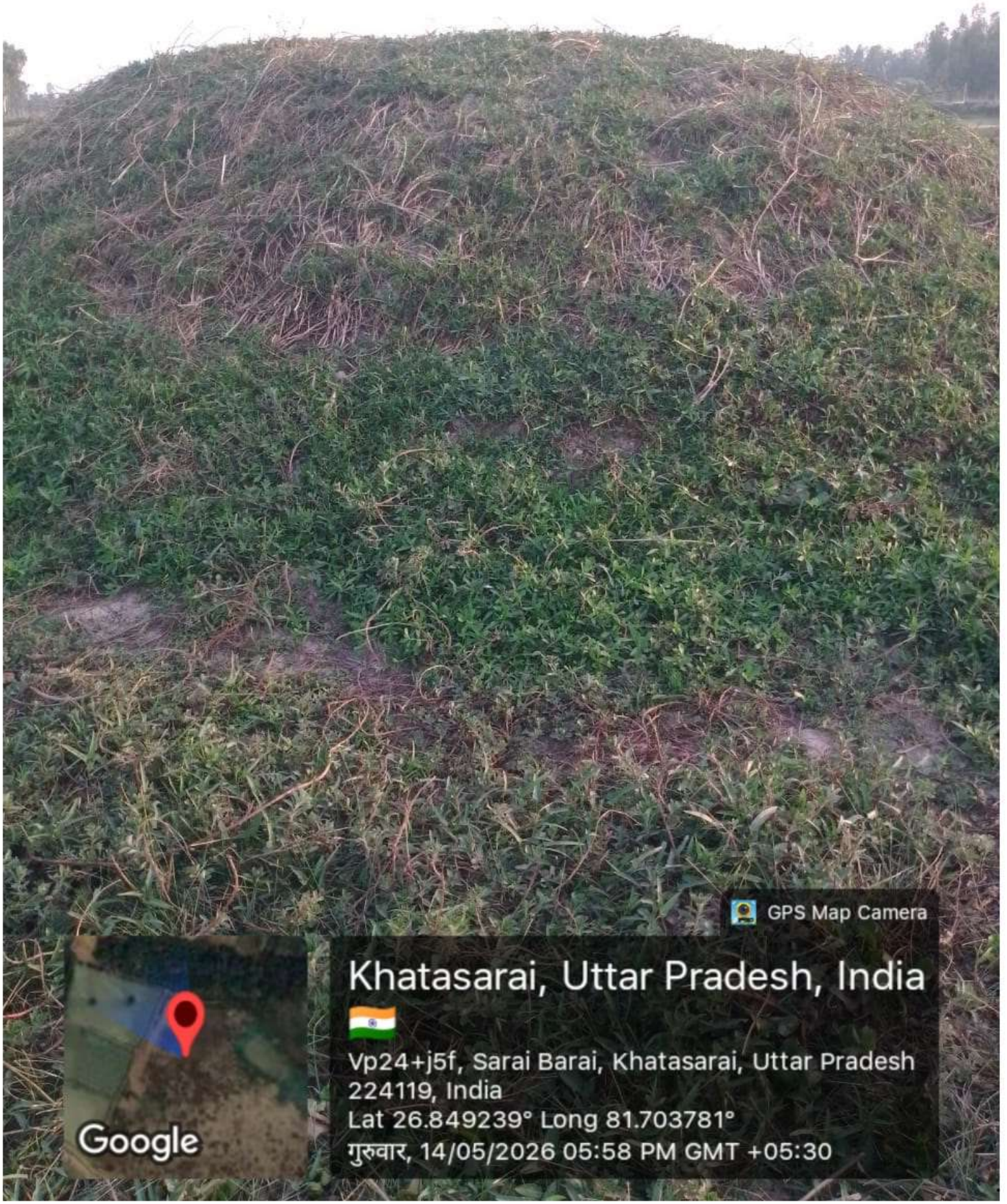
GPS Map Camera
Khatasarai, Uttar Pradesh, India
Vp24+j5f, Sarai Barai, Khatasarai, Uttar Pradesh 224119, India
Lat 26.849239° Long 81.703781°
गुरुवार, 14/05/2026 05:58 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Chainpurwa, Uttar Pradesh, India
59h8+79w, Chainpurwa, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.179957° Long 81.364518°
शनिवार, 09/05/2026 12:13 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Chainpurwa, Uttar Pradesh, India
59h8+79w, Chainpurwa, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.179957° Long 81.364518°
शनिवार, 09/05/2026 12:13 PM GMT +05:30

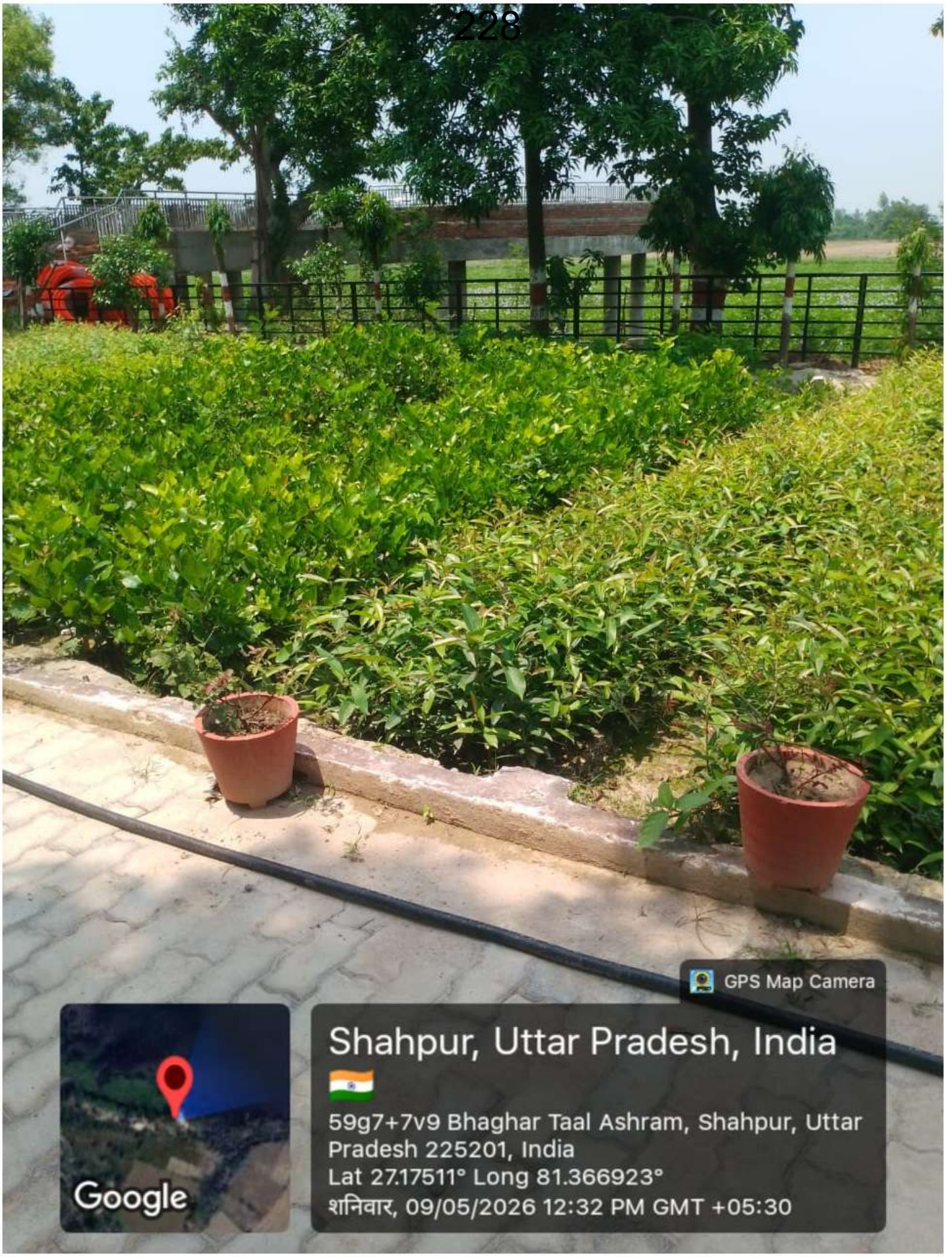
GPS Map Camera
Shahpur, Uttar Pradesh, India
59g7+7v9 Bhaghar Taal Ashram, Shahpur, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.17511° Long 81.366923°
शनिवार, 09/05/2026 12:32 PM GMT +05:30
Google

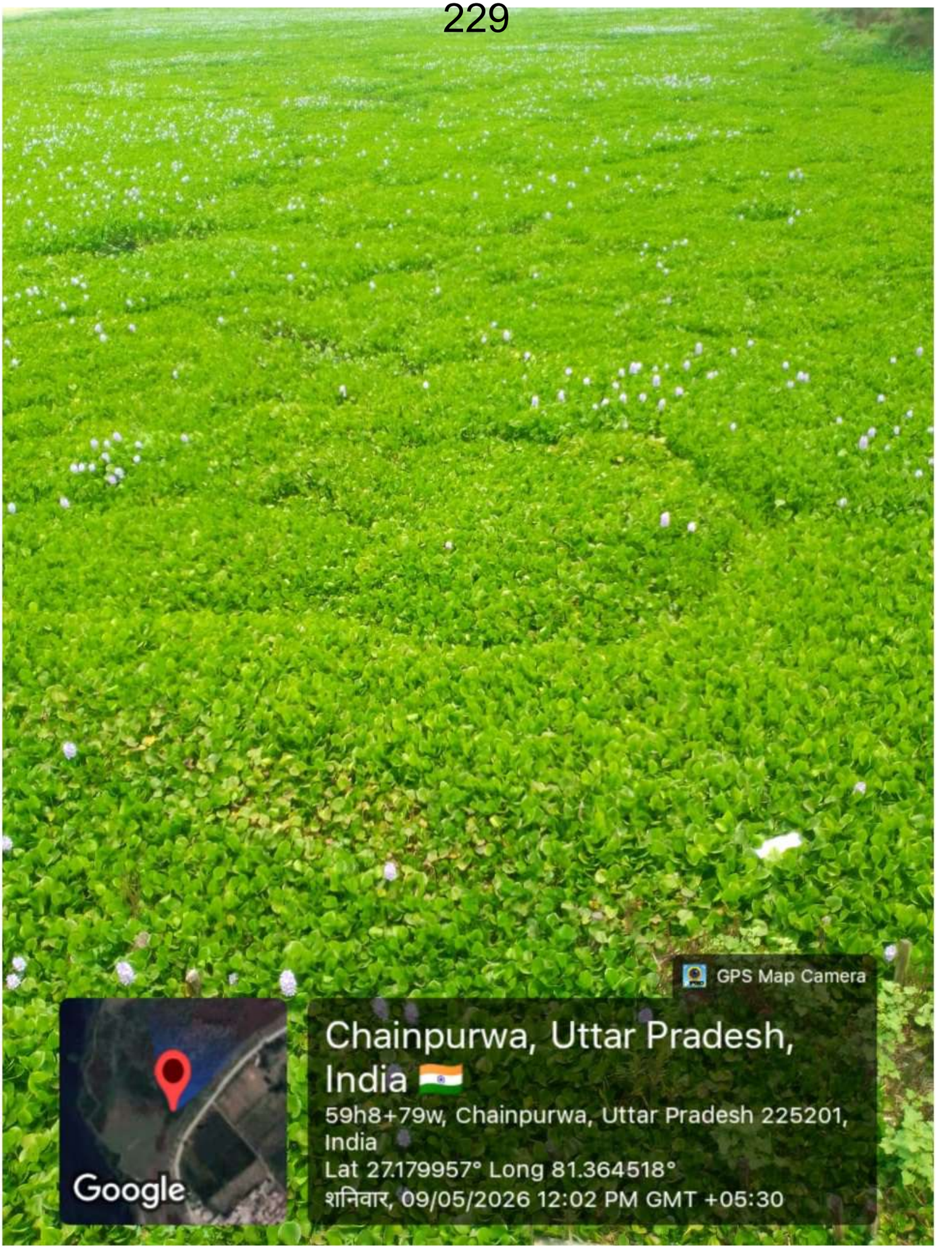
GPS Map Camera
Chainpurwa, Uttar Pradesh, India
59h8+79w, Chainpurwa, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.179957° Long 81.364518°
शनिवार, 09/05/2026 12:02 PM GMT +05:30
Google

P.T.O. 33

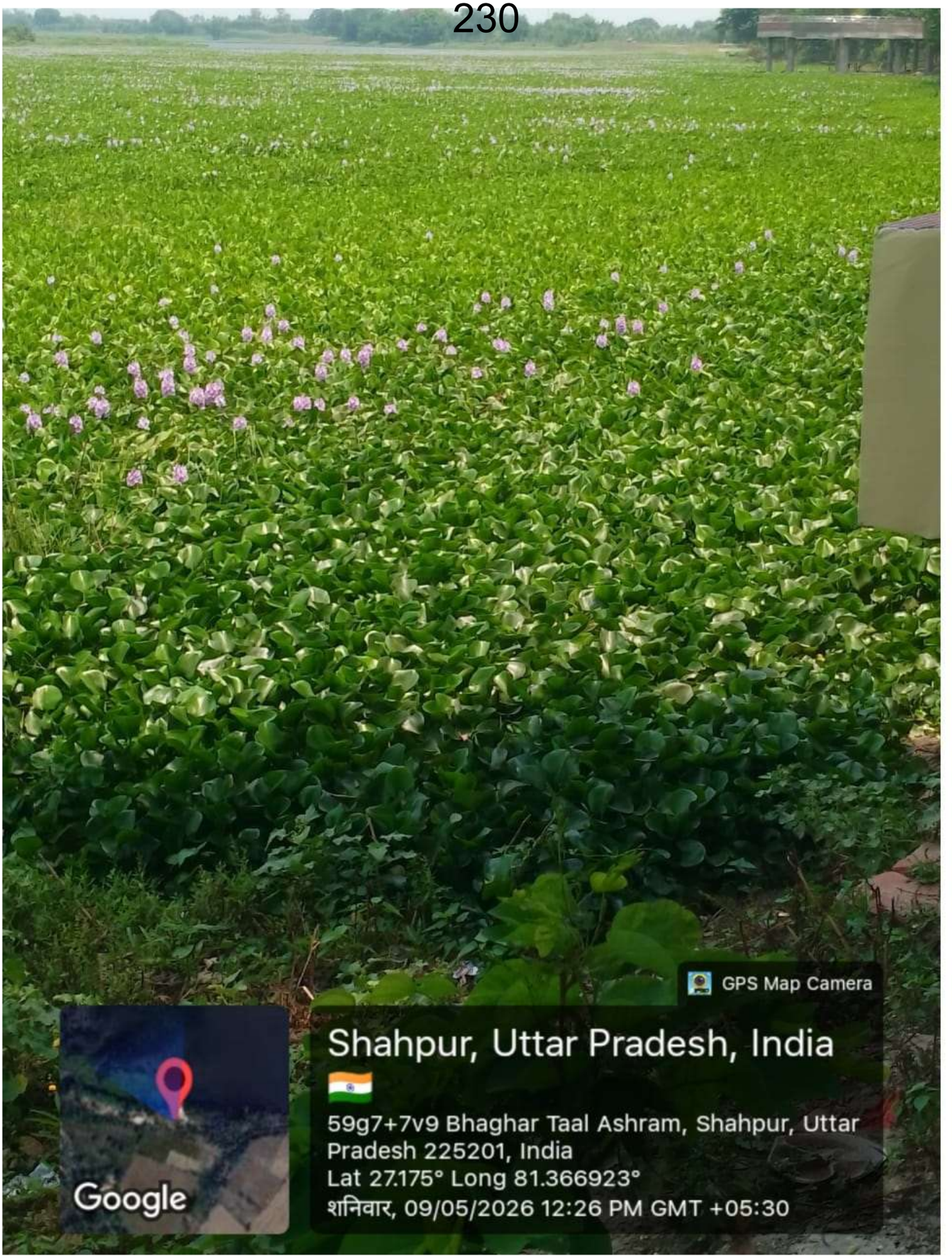
GPS Map Camera
Shahpur, Uttar Pradesh, India
59g7+7v9 Bhaghar Taal Ashram, Shahpur, Uttar Pradesh 225201, India
Lat 27.175° Long 81.366923°
शनिवार, 09/05/2026 12:26 PM GMT +05:30
Google